

प्रेषक,

डी०एस० गर्बाल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या- /XVIII(II)/2016-03(26)/20

सेवा में,

जिलाधिकारी,
चमोली।

राजस्व अनुभाग-2

विषय:- जनपद चमोली के अन्तर्गत तहसील कर्णप्रयाग के ग्राम जयकण्डी कालेश्वर में श्री बदरीनाथ-कैदारनाथ मन्दिर समिति के विश्राम गृह निर्माण हेतु कुल 0.105 है० भूमि श्री बदरीनाथ-कैदारनाथ मन्दिर समिति को निःशुल्क पट्टे पर आवंटन किये जाने के संबंध में।

देहरादून: दिनांक: 25 जुलाई, 2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-3202/छब्बीस-19(2011-2012) दि०-09.03.2016 तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं०-6792/पांच-भू०ह०/रा०प०-015 दि०-21.03.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, जनपद चमोली की तहसील कर्णप्रयाग के ग्राम जयकण्डी के नॉन जेड०ए० खाता खतौनी सं०-11 के खसरा सं०-455 मध्ये 0.105 है०, श्रेणी-9(3) ग गौचर भूमि को शासनादेश सं०-258/16(1)/73-राजस्व-1 दि०-09.05.1984, यथासंशोधित शासनादेश संख्या-1695/9 - 1-1(60)/93-280-रा०-1 दिनांक-12.09.1997 तथा शासनादेश सं०-1115/XVIII(II)/2016-18(184)/2015 दिनांक-15.06.2016 में दिये गये प्राविधानों को शिथिल करते हुए केवल मालगुजारी के 20 गुने के बराबर वार्षिक किराया निर्धारित कर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन श्री बदरीनाथ-कैदारनाथ मन्दिर समिति को पट्टे पर निःशुल्क आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।
2. प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
3. प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-150/1/85(24)-रा-6 दिनांक-09 अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30-30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1-1/2 गुना से कम नहीं होगा।
4. यदि प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
5. यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भागों से मुक्त निहित हो जायेगी।
6. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
7. प्रश्नगत नॉन जेड०ए० भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 के समकक्ष एवं सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8. चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि०-9.5.1984 के प्रस्तर तीन में निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

9. इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस०एल०पी०)/सी संख्या- 3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील संख्या-436/2011(एस०एल०पी०)(सी) संख्या-20203/2007 झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच एवं अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

10. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०एस० गब्याल)
सचिव।

पू०प०सं०- 614 / XVIII(II) / 2016-03(26) / 2016 तददिनांकित
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, धर्मस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. निजी सचिव, मा० डिप्टी स्पीकर, उत्तराखण्ड विधान सभा, देहरादून।
5. मुख्य कार्याधिकारी, श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति, जनपद चमोली।
6. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय।
7. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे०पी० जोशी)
अपर सचिव।